S.N	. Name of the State	No. of Inmates
4.	Bihar	950*
5.	Goa	85*
6.	Gujarat	85
7.	Haryana	86
8.	Himachal Pradesh	29
9.	Kamataka	2431
10.	Kerala	351
11.	Jammu & Kashmir	—
12.	Madhya Pradesh	166
13.	Maharashtra	7215
14.	Manipur	—
15.	Meghalaya	—
16.	Mizoram	45
17.	Nagaland	125
18.	Orissa	49
19.	Punjab	296*
20.	Rajasthan	73
21.	Sikkim	—
22.	Tamil Nadu	4000*
23.	Tripura	—
24.	Uttar Pradesh	1969
25.	West Bengal	3500*
26.	Andaman & Nicobar	—
27.	Chandigarh	3
28.	Delhi	942
29.	Pondicherry	110
30.	Dadra and Nagar Haveli	—
31.	Daman & Diu	—
32.	Lakshdweep	—
		23,151

*(Total No. of inmates maintained in Observation Homes, Juveniles Homes and Special Homes)

गुजरात में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

3433. **श्री जनार्दन चादव:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य है;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकार ने इंजीनियरिंग तथा मेडिकल कालेजों जैसे व्यावसायिक संस्थानों में भी 17 प्रतिशत आरक्षण कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार इंजिनियरिंग, मेडिकल कालेजों तथा अन्य शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ देने का विचार रखती है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) यह मामला विचाराधीन है।

Special drive to enroll children

3434. SHRIMATI CHANDRA KALAPANDEY:
SHRI MD. SALIM:

Will the Minister of WELFARE be pleasd to state:

(a) whether there is any plan to launch a special drive to enroll all the children in the age group of 6 to 14 belonging to SC / ST and OBC;

(b) if so, when this programme is going to be launched or by when the drive will be completed; and

(c) if not, how the Government propose to ensure the fulfilment of electoral promises?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) to (c). The National Policy on Education (NPE), 1986 as updated in 1992, resolves to ensure that free and compulsory education of satisfactory quality is provided to all children, including SCs / STs and OBCs, upto 14 years of age before the 21st century. The programme of Action, 1992 prepared in pursuance of the modified NPE contains the detailed programmes for achieving universal elementary education. At the beginning of every academic session, teachers are required to organise drives to enroll all school age children, especially girls belonging to SCs, STs and other backward sections. This is a continuous process and part of the effort to ensure universalisation of primary education.

अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग आयोगों में कर्मचारियों की कमी

3435. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अल्पसंख्यक आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग में कर्मचारियों की कमी के कारण ये दोनों संस्थायें ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही हैं;

(ख) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) दोनों संस्थाओं में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?